

1	विभाग का नाम	खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग
2	योजना का नाम	मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना
3	योजना की संक्षिप्त टिप्पणी	ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने, ग्रामीण शिक्षितों का शहर की ओर पलायन को हतोत्साहित करने तथा अधिक से अधिक रोजगार का अवसर गाँव में ही उपलब्ध कराने के ध्येय से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तिगत उद्यमियों को ₹0 10.00 लाख तक की वित्तीय सहायता बैंको के माध्यम से प्रदान की जाती है। योजना के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु 4 प्रतिशत से अधिक ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में उपलब्ध करायी जाती है। आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों (अनुसूचित जाति, अनु जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, महिलाएँ एवं भूतपूर्व सैनिक) को जिला योजना के अन्तर्गत ब्याज की पूर्ण धनराशि ब्याज उपादान के रूप में उपलब्ध करायी जाती है। व्यवसायिक बैंको तथा ग्रामीण बैंको द्वारा उनके सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत सम्बन्धित गाँव या ग्रामीण क्षेत्र स्थित हो, नियतानुसार ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जनपदों में जिलाधिकारी के सीधे नियंत्रण में खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग द्वारा क्रियान्वित की जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत सभी पात्र उद्यमियों को सावधि ऋण / कार्यशील पूंजी सम्मिलित करते हुये ₹0 10.00 लाख तक के बैंक ऋण पर ब्याज उपादान देय होता है। सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत अंशदान तथा अनुसूचित जाति / जनजाति / पिछड़ा वर्ग / महिला / विकलांग / अल्पसंख्यक / भूतपूर्व सैनिक वर्ग के उद्यमियों को प्रोजेक्ट लागत का 5 प्रतिशत अंशदान स्वयं वहन करना होगा।
4	पात्रता की अर्हता	<p>योजना के अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित वरीयता क्रम में उद्यमियों को लाभान्वित किया जायेगा।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आई0टी0आई0व पॉलीटेक्निक संस्थाओं से तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार नवयुवकों / नवयुवतियों को योजना में प्राथमिकता दी जायेगी 2. शिक्षित बेरोजगार नवयुवक जिनकी सरकारी सेवा की आयु समाप्त हो गई हो। 3. एस0जी0एस0वाई0 तथा शासन की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थी। 4. परम्परागत कारीगर। 5. स्वयं रोजगार में रुचि रखने वाली महिलाएँ। 6. व्यवसायिक शिक्षा (102) के अन्तर्गत ग्रामोद्योग विषय लेकर उत्तीर्ण। 7. इस योजना के अन्तर्गत उन अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जा सकता है जिन्होंने रोजगार हेतु सेवायोजन कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन सम्बन्धित जिलों के सेवा योजन कार्यालय में करा रखा है। <p>5. लाभार्थियों का चयन उ0प्र0खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड / शासन द्वारा समय समय पर गठित चयन समिति द्वारा या जिले स्तर पर अन्य राज्य पुरोनिधनित योजना / योजनाओं हेतु जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी / परगना अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा चयनित उद्यमी ही इस योजना के पात्र होते हैं। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उद्यमी को ऋण लेने से पूर्व वांछित प्रशिक्षण प्राप्त हो और उसके पास स्वयं का अंशदान उपलब्ध हो, तथा यह मूल रूप से ग्राम का निवासी हो, अथवा ग्रामीण क्षेत्र में अपना उद्योग लगाना चाहता हो।</p> <p>लाभार्थियों के चयन के मापदण्ड</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. लाभार्थियों की आयु 18 वर्ष से कम नहीं, तथा 50 वर्ष से अधिक न हो। 2. 50 प्रतिशत तक अनुसूचित जाति / जनजाति / पिछड़ा वर्ग के लाभार्थी। 3. स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता का आंकलन करके चयनित व्यक्तियों के लिये ग्रामोद्योग इकाई निर्धारित की जाती है। 4. स्थानीय उपभोगताओं की दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के उत्पादन करने सम्बन्धी इकाईयों स्थापित करने में वरीयता दी जायेगी।
5	आवेदन करने की प्रक्रिया	योजना के प्रस्तर 4 के अन्तर्गत वर्णित पात्र उद्यमियों के ऋण प्रार्थना-पत्र विभिन्न संस्थाओं/उद्यमियों के व्यक्तिगत सम्पर्क/विभिन्न राजकीय विभागों व स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति द्वारा समय-समय पर जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाती है। ऋण प्रार्थना पत्र यथा सम्भव बैंकों द्वारा निर्धारित प्रार्थना-पत्र पर लिया जाता है। यदि प्रार्थना-पत्र मिलने में असुविधा होती है तो बोर्ड द्वारा व्यक्तिगत उद्यमियों के प्रार्थना पत्र प्रयोग में लाये जाते हैं। जिनसे बाद में बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र प्राप्त कर लिया जाता है।
6	लिंक वेबसाइट	http://www.kviconline.gov.in/
7	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी अथवा परिक्षेत्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी, मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है।